


26.12.25

पत्रावली पास्के मिण्डि सा.ष लु पेरा दुर्गि अयथ  
पत्र उफा सा.ष दाय ॥ व आरेण ७ दिमद ॥ (१८  
स्वीकार दावा खारिद डिम जता हो विद्वत मिण्डि अला  
से शात्रिल डिम गमा डिफो जाति हो पत्रावली नं०  
से ह्य हो

आरेण सुनम गमा

  
सपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ (राज.)

GICMS  
2022/428



फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

रामस्वरूप बनाम मोहनी देवी आदि  
किस्म मुकदमा:-88,53,188 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:- 104/2022 (2022/428)

G.C.M.S

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.2025	<p>पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इन्ही वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य, इसी रकबा का इन्ही धारा 88-53 आर.टी.ए. में इसी न्यायालय में जैरकार था, जिसमें दिनांक 18.05.2007 को दावा व प्रतिदावा स्वीकार कर उक्त रकबा में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा घोषित कर दिया व खाता विभाजन हेतु श्रीमान् तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया था तथा इसी निर्णय अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी थी। इस निर्णय एव डिक्री के खिलाफ श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील नं. 133/15 रामेती देवी बनाम रामस्वरूप पेश हुई, जो दिनांक 04.08.2016 को खारिज हो गई, जिसकी द्वितीय अपील नं0 6575/2016 रामेती देवी बनाम रामस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है जिसमें आगामी पेशी 22.12.2025 नियत है इसलिए जब इस रकबा का इन्ही पक्षकारों के मध्य इन्ही धाराओं में दावा निर्णित हो चुका है तो पुनः नया दावा नहीं चल सकता इसलिए इस दावा को पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर तथा वाद कारण के अभाव में खारिज किया जावे।</p> <p>अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने बहस में निवेदन किया कि पूर्व निर्णय की पालना में व इस वाद में पुनः प्राथमिक डिक्री जारी कर वादी अपना खाता विभाजन चाहता है, प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय की पालना में अभी तक विभाजन प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए वादी को नया दावा पेश करना पड़ा है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी खारिज कर इस वाद का जवाब दावा लिया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।</p> <p>उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह बात साबित है कि इसी रकबा का इन्ही पक्षकारों के मध्य इन्ही धाराओं में पूर्व में दावा नं0 76/03 रामस्वरूप बनाम मोहनी अनवानी वाद में दिनांक 18.05.2007 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है तथा उस निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील नं0 6575/2016 रामेती बनाम रामस्वरूप जैरकार है तथा दिनांक 17.10.2016 से अपील में स्थगन भी जारी है इसलिए जब इन्ही पक्षकारों के मध्य इसी रकबा का घोषणात्मक दावा निर्णित होकर प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है तो पुनः अप्रार्थी/वादी को नया दावा पेश करने का वाद कारण पैदा नहीं होता तथा यह दावा पूर्व न्याय के सिद्धान्तों से भी बाधित है इसलिए हम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा इसी स्तर पर खारिज करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वाद वादीगण पूर्व न्याय के सिद्धान्तों से बाधित होने से व वाद कारण के अभाव में दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान से भी प्रतिबन्धित होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



B  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री ::-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
(पीठासीन अधिकारी :-भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

-:: अनवान ::-

1. रामस्वरूप पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

-वादी

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी गंगाराम
2. रामकुमारी पुत्री गंगाराम
3. रामकला पुत्री गंगाराम
4. रामेती पुत्री गंगाराम
5. रामदेई पुत्री गंगाराम
6. रामदुलारी पुत्री गंगाराम
7. रामनारायणी पुत्री गंगाराम
8. राममुर्ती पुत्री गंगाराम
9. रामरखी पुत्री गंगाराम
10. विक्रम पुत्र केसराराम
11. विनोद कुमार पुत्र केसराराम
12. शाखा प्रबन्धक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्तमान पीएनबी शाखा बीरमाना
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

-प्रतिवादीगण



वाद पत्र धारा-88,53,188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 104 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री कमलदत्त शर्मा तथा वकील प्रतिवादी श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

“वाद वादीगण पूर्व न्याय के सिद्धान्तो से बाधित होने से व वाद कारण के अभाव में दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान से भी प्रतिबन्धित होने से खारीज किया जाता है।”

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह..... x..... फस्टों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.12.2025 को जारी की गई।

*B*  
(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)  
सूरतगढ़